भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3004
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

डिजिटल पहुंच और नियोजनीयता के विस्तार के लिए डिजिटल कौशल पहल

3004. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार डिजिटल पहुंच और नियोजनीयता का विस्तार करने के लिए डिजिटल इंडिया, भारतनेट, पीएम-वाणी और एमईआईटीवाई डिजिटल कौशल पहल का कार्यान्वयन कर रही है;
(ख) क्या खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में भारतनेट फाइबर, लास्ट-माइल वाई-फाई, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चल रहे हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;
(ग) किसानों, महिलाओं, स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को डिजिटल भुगतान, ई-मार्केट, ई-गवर्नेंस और टेली-सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) यदि डिजिटल समावेशन और उपयोग कम रहता है तो पहचान की गई प्रमुख बाधाएं क्या हैं और उन्हें ठीक करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) इन जिलों में एमईआईटीवाई कौशल, सीएससी प्रचालनों और स्टार्ट-अप सहायता को स्थानीय रोजगार सृजन और सूक्ष्म उद्यम अवसरों से जोड़ने की क्या कार्यनीति है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसे प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था कि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

1. सामान्य सेवा केंद्र

सीएससी डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि होती है। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जनवरी, 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.54 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.32 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में 40,954 सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें कटनी में 941 सीएससी, पन्ना में 633 सीएससी और छतरपुर जिले में 1567 सीएससी (खजुराहो क्षेत्र सहित) शामिल हैं।

सीएससी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिलावार ब्यौरा https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है और सेवाओं की सूची https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है_।

2. डिजिटल स्किलिंग: सरकार ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं और नवीनतम तकनीकों में स्किलिंग/अपस्किलिंग के लिए कार्यक्रम चलाती है। प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

(i) पीएमजीदिशा: डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लागू की गई थी और यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई।

यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक के रूप में उभरी है, जिसमें देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है (6 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले)।

मध्य प्रदेश राज्य में, ग्रामीण परिवारों के कुल 56,92,467 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया था, और 50,69,449 उम्मीदवारों को योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया था।

इसमें कटनी से 92,755 उम्मीदवार, पन्ना से 94,679 और छतरपुर जिले (खजुराहो क्षेत्र सहित) से 137205 उम्मीदवार शामिल थे।

(ii) **फ्यूचरस्किल्स प्राइम:** यह एमईआईटीवाई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य भारत को एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभा राष्ट्र बनाना है। प्रमुख विशेषताएं हैं:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (एआर/वीआर) आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करता है।
- वास्तविक रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं।
- पोर्टल को उनकी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए https://futureskillsprime.in/ पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

कार्यक्रम के तहत, अब तक, पोर्टल पर 27.53+ लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 17.24+ लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया है।

मध्य प्रदेश राज्य में, कुल 50,000 से अधिक उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण लिया है

(iii) **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)**

नाइलिट डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटर अवधारणा में जागरूकता (एसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) आदि प्रदान करता है। इसने डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत 43 लाख+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

प्रशिक्षण 56 नाइलिट केंद्रों और 9000+ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों/सुविधा केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

नाइलिट के मध्य प्रदेश राज्य में फैले 350 से अधिक सुविधा केंद्र हैं, जिनमें से लगभग 15 केंद्र डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों (डीएलसी) को बढ़ावा देने के लिए कटनी और पन्ना जिलों में स्थित हैं।

2020 और 2025 के बीच, मध्य प्रदेश राज्य में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों के लिए कुल 66,404 उम्मीदवारों ने आवेदन किया।

इसके अलावा, उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य फ्रंटियर डोमेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार, उद्योग-संरेखित कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म में सेमीकंडक्टर डिजाइन, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, उद्योग 4.0 और अन्य उभरते डोमेन में वास्तविक समय के प्रयोग के लिए अंतर्निहित वर्चुअल लैब भी हैं।

एनडीयू प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रत्येक शिक्षार्थी एनएसक्यूएफ-संरेखित पाठ्यक्रमों तक कभी भी-कहीं भी पहुंच प्राप्त कर सकता है। अब तक 55,000 से अधिक उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एनडीयू प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कराया है।

3. बुनियादी संचार/इंटरनेट सेवाएं: ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में इंटरनेट की पहुंच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा वायरलेस मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के माध्यम से प्रदान की जाती है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने मोबाइल नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर बुनियादी ढांचे के विस्तार के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं:

(i) **भारतनेट:** पूरे देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

नेटवर्क का उपयोग बैंडविड्थ और डार्क फाइबर को पट्टे पर देने और सार्वजनिक स्थानों पर ब्रॉडबैंड और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई के प्रावधान के माध्यम से किया जाता है।

यह सरकारी संस्थानों (जैसे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ियों, पुलिस स्टेशनों, कृषि विज्ञान केंद्रों, डाकघरों, राशन की दुकानों) के साथ-साथ निजी संस्थानों और घरों के लिए फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी का भी समर्थन करता है।

अब तक कुल 2,14,921 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है, जिनमें कटनी में 115 ग्राम पंचायतें, पन्ना में 390 ग्राम पंचायतें और छतरपुर जिले (खजुराहो क्षेत्र सहित) में 225 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(ii) **प्रधान मंत्री वाई-फाई अभिगम नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी)** में एक ढांचा उपलब्ध कराया गया है जो सार्वजनिक डाटा कार्यालयों (पीडीओ) को न्यूनतम विनियामक निगरानी के साथ सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीओडीए) और एप्लिकेशन प्रदाताओं के एकत्रीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है। यह फ्रेमवर्क दुकानदारों और छोटे उद्यमों को डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

02.03.2026 तक, स्थापित पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या कटनी में 76, पन्ना में 40 और छतरपुर में 89 है।

सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को डिजिटल भुगतान, ई-बाजार, ई-गवर्नेंस सेवाओं और टेली-सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क). **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक हर समय पहुंच प्रदान करता है।

67.17+ करोड़ उपयोगकर्ता डिजिलॉकर के साथ इसकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पर शामिल 2456 जारीकर्ताओं से 967.01+ करोड़ दस्तावेज जारी किए गए हैं।

(ख). **सामान्य सेवा केंद्र**: सीएससी डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि होती है। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जनवरी, 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.54 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.32 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)** यह सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। प्लेटफ़ॉर्म पर 2446 से अधिक सेवाएं (केंद्रीय: 872, राज्य: 1,574) की पेशकश की जाती है।

(घ) **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज़, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यूपीआई 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है, और 685 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है। यह भारत के 81% डिजिटल भुगतान और वैश्विक वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान के लगभग 49% को शक्ति प्रदान करता है।

(ङ) **लोकओएस एप्लीकेशन:** इसे देश भर में स्व-सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्कों के एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है।

5.58 लाख ग्राम संगठनों (वीओ) सहित 93 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। इन समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) के माध्यम से जुटाए गए 10.11 करोड़ से अधिक परिवारों को लोकओएस से जोड़ा गया है।

(च) **पोषण ट्रैकर:** यह महिलाओं और बाल विकास और पोषण सेवाओं के अंतिम छोर तक वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह लाभार्थियों और कर्तव्य वाहकों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग प्रदान करता है और सक्रिय सेवा वितरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है।

प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 13.36 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अंतिम छोर तक सेवा वितरण के साथ 8.90 करोड़ लाभार्थियों को पोषण सेवाएं प्रदान की गई हैं।

(छ) **ई-संजीवनी** - भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समानता की दिशा में एक कदम है। ई-संजीवनी स्मार्टफोन से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

18,500+ हब के माध्यम से 138,300+ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (प्रवक्ता के रूप में) में 45.43 करोड़ से अधिक रोगियों को टेलीमेडिसिन चिकित्सकों के रूप में 230,800+ डॉक्टरों, चिकित्सा विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा प्रदान की गई।

(ज) **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम):** जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

वर्तमान में, 135,800+ प्राथमिक खरीदार और 208,400+ माध्यमिक खरीदार जीईएम पर शामिल हैं। जीईएम पर 10,700+ उत्पाद श्रेणियां और 355 सेवा श्रेणियां सूचीबद्ध की गई हैं।

(झ) **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)** ई-नाम बाजारों तक पहुंच, वास्तविक समय मूल्य सूचना प्रदान करता है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता परख की सुविधा प्रदान करता है और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग के लिए अवसंरचना प्रदान करता है।

अब तक, छोटे किसानों सहित 1.79 करोड़ किसान ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं और 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1522 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है।

*****